	कार्यक्रम	वर्ष	आबंटन (केन्द्र + राज्य) (लाख रुपयों में)	भौतिक उपलब्धियां		
		1992-93	6822.00	1840.83	,,	
		1993-94	10342.00	242673	,,	
2.	जवाहर रोजगार योजना	1991-92	23885.31*	945.39	(लाख श्रम दिवस)	
		1992-93	33629.94*	709.66	,,	
		1993-94	31062.44*	769.25	,,	
3.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	1991-92	3683.00*	5877	(कवर किए गए गांवों की संख्या)	
		1992-93	2738.40*	5866	,,	
		1993-94	4933.70*	5963	,,	
						(80 हैक्टेयर में)
				एलआरडी	डब्लूआरडी	एएफएफ
4.	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1991-92	809.00	53.80	0.61	66.90
		1992-93	809.00	30.39	6.70	59.95
		1993-94	1213.50	26.35	9.68	54.07

* आकड़े की गई रिलीजों से संबंधित हैं।
एलआरडी—भूमि संसाधन विकास
डब्लूआरडी—जल संसाधन विकास
एएफएफ—वन रोपण एवं चरागाह विकास

मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास योजना

4197. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला-वार निर्धारित/प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई नई योजना शुरू करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस प्रयोजन के लिए जिला-वार उपलब्ध कराई गई धनराशि कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) मध्य प्रदेश में शुरू की गई महिला एवं शिशु विकास योजना 40 जिलों मे कार्यान्वित की जा रही है। यह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-योजना है जिसके तहत् 5.15 ग्रामीण गरीब महिलाओं के समूहों को आय बढ़ाने वाली स्वरोजगार की गतिविधियां चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक समूह को 25,000 रुपये तक की आवर्ती निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। मंत्रालय द्वारा जिले-वार ब्यौरों की निगरानी नहीं रखी जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	बनाए जाने वाले समूहों की संख्या	बनाए गए समूह
1991-92	1150	1167
1992-93	810	529
1993-94	832	901

(ग) जी, नहीं

(घ) लागू नहीं होता।

Potable water to SCs/STs in Gujarat

4198. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what target was fixed for the supply of potable water to persons belonging to SC-ST communities in rural and tribal areas of Gujarat during the Seventh Five Year Plan and the extent to which the same has been achieved;

(b) what target has been fixed to sort out the problem of potable water during the Eighth Five Year Plan; and

(c) the details of villages in the States which are proposed to be provided with potable water during the Eighth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) During the VII Five Year Plan the target and achievement of Rural Water Supply in terms of coverage of villages and population in Gujarat was as under:—

Villages	Total Rural population (in lakh)	SCs out of (2)	STs out of (2)
5863	TARGET 51.09	3.83	7.21
6474	ACHIEVEMENT 65.61	5.51	7.16

(b) and (c) The target for coverage of villages and rural population in Gujarat during 1992-93, 1993-94, 1994-95 and 1994-95 is as under:—

Villages	Population (in lakh) Total	SCs out of (2)	STs out of (2)
	1992-93		
500	7.420	0.560	0.820
	1993-94		
500	6.300	1.058	0.630
	1994-95		
500	5.400	0.360	0.500

The target for 1995-96 and 1996-97 will be decided on year-to year basis depending upon the outlay of funds for these years.

Jawahar Rozgar Yojana in Gujarat and Maharashtra

4199. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 20% of the total allocation made to Gujarat and Maharashtra under the Jawahar Rozgar Yojana is being utilised for digging wells and most of this amount is being wasted;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any record was maintained to find out the working under this programme during the last three years;

(d) if so, the number of wells dug in Gujarat and Maharashtra during the last three years and the percentage of total amount allocated to Gujarat and Maharashtra under Jawahar Rozgar Yojana being spent on digging wells, district-wise; and

(e) whether any new initiative is being taken to check the wasteful expenditure?